



Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 28 जनवरी, 2021

गुईसेपे कॉटे

कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुईसेपे कॉटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। गुईसेपे कॉटे को वर्ष 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व उन्होंने अपने कैरियर का अधिकांश हिस्सा कानून के प्रोफेसर के रूप में बताया और वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के बीच वे इतालवी प्रशासनिक ब्यूरो के सदस्य भी रहे। ज्ञात हो कि इटली की सरकार महामारी के कारण गंभीर दबाव का सामना कर रही थी, कोरोना महामारी के प्रकोप की शुरुआत के बाद से इटली में लगभग 85,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, साथ ही महामारी का इटली की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके कारण सरकार को उच्च बेरोजगारी और सार्वजनिक ऋण जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। इटली आपेननीनी (Apennine) प्रायद्वीप पर दक्षिणी यूरोप में स्थित है। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, वेटकिन सट्टी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया और स्वट्ज़रलैंड के साथ इटली अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भूमध्यसागर में मौजूद सबसे बड़े द्वीपों में से दो द्वीप यथा- सिसिली और सार्डिनिया इटली से ही संबंध हैं।

वरचुअल इंटेल्जिंस टूल: तेजस

नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्वसिंज इंफॉरपोरेटेड (NICS) की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रवशंकर प्रसाद द्वारा 'तेजस' नाम से एक वरचुअल इंटेल्जिंस टूल लॉन्च किया गया, जो कनिगरकों को नीतगित नरिणयों और सरकारी सेवाओं एवं उनके वतिरण से जुड़ी दक्षता में सुधार के उद्देश्य से सार्थक जानकारी जुटाने के लिये उपलब्ध डेटा के माध्यम से महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री द्वारा 'ई-नीलामी भारत' (यह सरकारी संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक फारवरड और रविर्स नीलामी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 24x7 ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराएगी) और 'वरक फ्रॉम एनीवेयर' पोर्टल भी लॉन्च किया गया, यह पोर्टल महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और काम की सुगमता सुनिश्चित करने के लिये वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से संचार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्वसिंज इंफॉरपोरेटेड, [राष्ट्रीय सूचना वजिज्ञान केंद्र](#) (NIC) के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपकरण है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र एवं राज्य सरकारों और देश भर के अन्य सार्वजनिक उपकरणों को ई-गवर्नेंस से जुड़ी परियोजनाओं के लिये एंड-टू-एंड आईटी समाधान प्रदान करना है।

आयुष्मान CAPF

केंद्रीय गृह मंत्री अमति शाह ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के कर्मियों और उनके परिवारजनों के लिये 'आयुष्मान CAPF' योजना की शुरुआत की है। यह योजना असम के गुवाहाटी में CAPF समूह केंद्र में शुरू की गई है। इस योजना के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के 50 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत CAPF कर्मी और उनके परिवार के सदस्य देश भर के 24,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में पूर्णतः पेपरलेस और कैशलेस सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के मामले में प्रतियुक्ति की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। असम राइफलस, सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय रज़िर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और भारत-तबिबत सीमा पुलिस (ITBP) के कर्मियों और उनके आश्रितों को योजना के तहत कवर किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय कस्टम दविस

26 जनवरी, 2021 को वशिव भर में अंतरराष्ट्रीय कस्टम दविस का आयोजन किया गया। इस वर्ष यह दविस 'एक टकिऊ आपूर्ति शृंखला के लिये सीमा शुल्क वसूली में तेज़ी, नवीकरण और लचीलापन' थीम के साथ आयोजित किया गया। यह दविस वशिव भर की सीमाओं पर वस्तु और माल के प्रवाह की देखभाल के कार्य के लिये कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों को सम्मानित करता है। [वशिव सीमा शुल्क संगठन](#) (WCO) द्वारा गठित यह दविस वर्ष 1953 में बेलजियम के ब्रुसेल्स में आयोजित सीमा शुल्क सहयोग परिषद (CCC) के उद्घाटन सत्र की शुरुआत को चहिनति करता है। वर्ष 1994 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का नाम बदलकर वशिव सीमा शुल्क संगठन (WCO) कर दिया गया। यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है और वर्तमान में इसके कुल 183 सदस्य हैं।

